दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रिट.या. (आप.) 3641/2023 में निर्णय सुरक्षित किया गया 11 दिसंबर, 2023 रिट .या. (आप.) 3657/2023 और 3662/2023 में निर्णय सुरक्षित किया गया : 12 दिसंबर, 2023

निर्णय दिया गया : 19 दिसंबर, 2023

रि. या. (आप.) 3641/2023, आप. वि.अ.. 33843/2023

नितिन गर्ग ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमन शर्मा, श्री समर्थ के. लूथरा, श्री अंकित भाटिया, श्री तरुण नेहरा, श्री विश्वजीत सिंह भाटी, सुश्री रुद्राली पाटिल और सुश्री अर्शिया घोष, अधिवक्तागण ।

बनाम

भारत संघ एवं अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुराग अहलूवालिया, सी. जी. एस. सी. के साथ श्री शिवम सचदेवा, भारत संघ के सरकारी अभिवक्ता, श्री जोहेब हुसैन, विशेष वकील श्री साइमन बेंजामिन, एस. पी. पी., श्री मनीष जैन, एस. पी.

पी., श्री विवेक गुरनानी, श्री कार्तिक सभरवाल और श्री वैभव, ईडी के अधिवक्तागण ।

और

रिट. या. (आप.) 3657/2023, आप.वि.अ. 34028/2023, आप.वि.अ. 34029/2023

ग्वांगवेन क्वांग उपनाम एंड्रू। .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री हरिहरन एन. वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री प्रियंक लाडोइया, श्री तन्मय शर्मा, श्री क्षितिज राव, श्री शारियन मुखर्जी, श्री मुईद शाह, श्री प्रतीक भालिया और सुश्री रेखा अंगारा, अधिवक्तागण

बनाम

राजस्व एवं अन्य एस. के प्रवर्तन विभाग का निदेश। ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, श्री विवेक गुरनानी के साथ विशेष वकील, श्री मनीष जैन, श्री साइमन बेंजामिन, श्री सौगत गांगुली, श्री अमित जैन, श्री ईशान बैसला, श्री कार्तिक सभरवाल, श्री वैभव और श्री विनोद

तिवारी, प्रत्यर्थी -1 के लिए अधिवक्तागण ।

और

रिट . या. (आप.) 3662/2023, आप.वि.अ. 34061/2023, आ.वि.अ. 34062/2023

प्रणय राय ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विक्रम चौधरी, वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता अभय राज वर्मा, श्री नीतेश राणा, श्री अर्जुन रेखी, श्री ऋषि सहगल, सुश्री अरवीन सेखों, सुश्री निकिता गिल और सुश्री मुस्कान खुराना, अधिवक्ता।

बनाम

प्रवर्तन निर्देशक एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वाराः श्री जोहेब हुसैन, श्री विवेक गुरनानी के साथ विशेष वकील, श्री मनीष जैन, श्री साइमन बेंजामिन, श्री सौगत गांगुली, श्री अमित जैन, श्री ईशान बैसला, श्री कार्तिक सभरवाल, श्री वैभव और श्री विनोद तिवारी, अधिवक्ता।आर-1 के लिए।

कोरमः

माननीय न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत माननीय न्यायाधीश शालिंदर कौर

निर्णय

न्या. शालिंदर कौर,

1. तीन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ अर्थात्, रिट.या. (आप.) 3641/2023, रिट.या.(आप.) 3657/2023 और रिट. या. (आप.) 3662/2023 को इस सामान्य निर्णय के माध्यम से एक साथ निपटाने के लिए लिया जा रहा है क्योंकि वे एक ही प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं जिसकी संख्या ई. सी. आई. आर./एस. टी. एफ./02/2022 [इसके बाद "ई. सी. आई. आर". के रूप में संदर्भित] और न्यायिक आदेश के अभाव में याचिकाकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए तिहाड़ जेल में अवैध रूप से हिरासत में रखने के संबंध में एक ही सवाल शामिल करता है । याचिकाकर्ता प्रत्यर्थियों को बंदी प्रत्यक्षीकरण या कोई अन्य उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,21 और 22 के तहत याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार का प्रत्यर्थियों द्वारा उल्लंघन किया गया है। उनकी निरंतर अवैध हिरासत निर्वात में होने के दोष से ग्रस्त है, क्योंकि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का कोई न्यायिक आदेश नहीं है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 [जिसे इसके बाद दं.प्र.संकहा गया है] या

यहां तक कि दं.प्र.सं के किसी प्रावधान के तहत भी अनिवार्य है। उनकी निरंतर अवैध नजरबंदी निर्वात में है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का कोई न्यायिक आदेश नहीं है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के तहत अनिवार्य है या अन्यथा किसी भी प्रावधान के तहत ऐसा किया जाता है । उन्हें जेल अधीक्षक, तिहाड़ जेल की हिरासत में भेजने के किसी भी न्यायिक आदेश की अनुपस्थिति में, उनकी नजरबंदी अवैध है। याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि वे याचिकाकर्ताओं को पेश करें और याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थियों की अवैध हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दें, जिससे याचिकाकर्ताओं की हिरासत को मनमाना और अवैध घोषित किया जा सके।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

2. वर्तमान याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए बुनियादी तथ्यों का वर्णन यह है कि निदेशालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद दं.प्र.सं" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत कथित रूप से किए गए अनुसूचित अपराध के आधार पर, पी. एम. एल. ए. की धारा 3 के तहत धन शोधन के कथित अपराध के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (इसके बाद "पी. एम. एल. ए". के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत एक ई. सी. आई. आर. दर्ज किया, जो पी. एम. एल. ए. की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

प्राथमिकी संख्या 2021 का 807, दिनांक 05.12.2021, पुलिस थाना कालकाजी, दक्षिण जिला, नई दिल्ली में दर्ज किया गया और प्राथमिकी संख्या. 2021 का 190, दिनांक 13.12.2021, पुलिस थाना आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली में पंजीकृत है।

याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुति

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ईसीआईआर में जांच के हिस्से के रूप में, याचिकाकर्ताओं और चौथे सह-आरोपी राजन मलिक को 10.10.2023 पर लेकिन अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पश्चात, धारा दं.प्र.सं के तहत अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ताओं को विद्वान **अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश** 05, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया - [इसके बाद "अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-05" के रूप में संदर्भित] आई. डी. 2 पर और याचिकाकर्ताओं की दस दिनों की हिरासत की मांग करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (इसके बाद "ई. डी". के रूप में संदर्भित) के आवेदन पर, तदनुसार विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-05 ने आई. डी. 1 तक तीन दिनों की हिरासत प्रदान की। इसके बाद, 13.10.2023 पर दायर आवेदन पर ईडी के पक्ष में 16.10.2023 तक तीन दिन की और हिरासत दी गई। अंत में, हिरासत को फिर से दो दिनों के लिए 18.10.2023 तक बढ़ा दिया गया, हालांकि ईडी द्वारा 10 दिनों के लिए मांगा गया था ।

4. यह आठ दिनों के लिए ईडी की कठिन हिरासत का सामना करने के बाद प्रस्तुत किया गया था, 18.10.2023 पर, ईडी ने विद्वान ए स जे -05 के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें याचिकाकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई थी जिसे 30.10.2023 तक की अवधि के लिए दिया गया था। अंत में 23.11.2023 पर, याचिकाकर्ताओं को चौदह दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ईडी द्वारा दायर एक नए आवेदन पर और याचिकाकर्ताओं को 07.12.2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजकर यह अनुमति दी गई।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि धारा 167 दं.प्र.सं के तहत जांच पूरी करने के लिए प्रदान की गई साठ दिनों की वैधानिक अवधि 08.12.2023 पर समाप्त होने वाली थी, हालांकि, ई. डी. ने 06.12.2023 पर पी. एम. एल. ए. की धारा 45 के साथ पठित धारा 44 के तहत, याचिकाकर्ताओं और चौथे सह-अभियुक्त अर्थात् राजन मलिक को अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत करते हुए, ई. सी. आई. आर. में 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम एम./एस. वीवो मोबाइल संचार कंपनी लिमिटेड (पी. सी.)' शीर्षक से मामला संख्या 102/2023 के साथ एक अभियोजन शिकायत दर्ज की। 07.12.2023 पर, एस. पी. पी. ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-05 को सूचित किया कि अभियोजन शिकायत ई. डी. द्वारा दायर की गई थी जो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट (अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-एस. एफ.

टी. सी.) की अदालत में सुनवाई के लिए आई थी और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-एस. एफ. टी. सी. ने अभियोजन शिकायत का संज्ञान नहीं लिया।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने आगे कहा कि 07.12.2023 पर याचिकाकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -05 के समक्ष पेश किया गया था। हालांकि, ईडी ने याचिकाकर्ता की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया । इसके विपरीत, ईडी ने अदालत को सूचित किया कि अभियोजन की शिकायत एक प्रशासनिक आदेश द्वारा से विद्वान प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 की अदालत को सौंपी गई थी और ईडी ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -05 से अनुरोध किया कि फाइल को उसी दिन विद्वानअतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 की अदालत में स्थानांतरित किया जाए, जिसे दोपहर 2 बजे लिया जाए। इसलिए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -05 द्वारा 07.12.2023 पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके वकीलों और ईडी के साथ एस. पी. पी. द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 के समक्ष पेश होने पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-04 ने दोपहर के भोजन के बाद संज्ञान के पहलू पर विचार करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सुनवाई की तारीख उक्त तारीख के लिए पेशी वारंट जारी किए।

7. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि निदेशालय ने याचिकाकर्ताओं की न्यायिक हिरासत के विस्तार की मांग करने वाला कोई भी आवेदन दायर करने की जहमत नहीं उठाई, जैसा कि कानून के तहत अनिवार्य है और याचिकाकर्ताओं की न्यायिक हिरासत के विस्तार की मांग करते हुए पिछले सभी अवसरों पर धार्मिक रूप से किया गया है। यह उपरोक्त के आलोक में जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया था, यह बहुत स्पष्ट है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-04 द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को आगे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जैसा कि 07.12.2023 से परे धारा 167 दं.प्र.सं के तहत अनिवार्य है।

8. श्री हरिहरन एन., विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-05 के समक्ष रिमांड फाइलों का निरीक्षण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वकील को सूचित किए बिना रिमांड के लिए कोई आवेदन दायर किया गया था और क्या विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-05 द्वारा रिमांड बढ़ाने का कोई आदेश पारित किया गया था। निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि रिमांड बढ़ाने की मांग करने वाला कोई आवेदन या उसी को दर्ज करने वाला कोई आदेश विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-05 द्वारा पारित नहीं किया गया था । निरोध/अभिरक्षा केवल एक अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है और किसी व्यक्ति की अभिरक्षा को मान्य करने के लिए

न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने वाले वैध न्यायिक आदेश को पारित करने की आवश्यकता होती है ।

9. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि ईडी ने 06.12.2023 को अदालत में अभियोजन दायर की है जो आगे दर्शाता है कि धारा 167 (2) दं.प्र.सं के तहत रिमांड ईडी द्वारा उक्त अभियोजन शिकायत/आरोप पत्र दायर करने के साथ समाप्त हो गई । हालाँकि, 07.12.2023 पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 ने उपरोक्त अभियोजन शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया और याचिकाकर्ताओं को धारा 309 दं.प्र.सं के तहत न्यायिक हिरासत में नहीं भेज सका, इसलिए, धारा 309 दं.प्र.सं के तहत विचार किया गया चरण शुरू नहीं हुआ। जिन मामलों में आरोप पत्र दायर किया जाता है, हालांकि, अदालत द्वारा किसी भी कारण से संज्ञान नहीं लिया जाता है, वहां आरोपी को धारा 167 (2) (ख) भा . दं.सं . के तहत प्रावधान के अनुसार जमानत का कोई अधिकार नहीं होगा, इस प्रकार धारा 167 भा.दं.सं के तहत उसकी रिमांड जारी रखने की आवश्यकता होगी। रिलायंस को रखा गया था **सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2013) 3 एस. सी. सी. 77] और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय** बनाम राहुल मोदी [2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 153] यह प्रस्तुत किया गया था चूंकि , धारा 167 (2) दं.प्र.सं या धारा 309 Cr.P.C के तहत न्यायिक हिरासत के रिमांड बढ़ाने के अलावा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-04 के पास याचिकाकर्ताओं को

न्यायिक हिरासत में भेजने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं की न्यायिक हिरासत 07.12.2023 तक न्यायिक आदेश द्वारा समर्थित नहीं है, यह अवैध है।

10. **राम नारायण सिंह बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य** के मामले पर भरोसा करते हुए [(1953) 1 एस. सी. सी. 389]यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल मामले को अगली तारीख तक स्थगित करने का आदेश जिसमें उस तारीख तक आरोपी को रिमांड पर लेने का कोई निर्देश नहीं है अन्य रिमांड के आदेश पर्याप्त नहीं है । इसलिए, किसी भी तरह की व्याख्या से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-04 द्वारा पारित 07.12.2023 के आदेश को न्यायिक हिरासत देने के रूप में नहीं माना या समझा जा सकता है। इसके विपरीत, 07.12.2022 को आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए उत्पादन वारंट जारी करने के लिए आगे बढ़ता है जो यह स्पष्ट करता है कि 07.12.2022 को, याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत देने वाले किसी भी न्यायिक आदेश के अनुसार हिरासत में नहीं थे।

11. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उत्पादन वारंट जारी करने की तुलना रिमांड के आदेश के साथ नहीं की जा सकती है जैसा कि ईडी की ओर से सुझाव दिया जा रहा है, क्योंकि उत्पादन वारंट का आदेश धारा 267 भा.दं. सं के तहत पारित किया जाता है, जबकि रिमांड आदेश की धारा 167 दं.प्र.सं या धारा 309 दं.प्र.सं के तहत दिया जाता है जो अलग-अलग तरीके से काम

करता है और उपरोक्त प्रावधानों को दं.प्र.सं में अलग-अलग अध्यायों के तहत रखा जाता है।

12. उपरोक्त दलीलों से सहमति जताते विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विक्रम चौधरी ने तर्क दिया कि रिमांड आदेश पारित करना एक न्यायिक कार्य है जिसे यांत्रिक रूप से या आकस्मिक तरीके से नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश न्यायिक अधिकारी द्वारा उचित विवेक के साथ पारित किया जाना है । इसलिए, याचिकाकर्ताओं की अभिरक्षा को दिनांक 07.12.2023 के आदेश द्वारा से बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को धारा 167 (2) (ख) दं.प्र.सं के उल्लंघन में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 के समक्ष पेश नहीं किया गया था, जिसके लिए अभिरक्षा रिमांड के विस्तार के समय आरोपी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से पेश करने की आवश्यकता होती है। **रमेश कुमार रवि उपनाम राम प्रसाद अन्य आदि बनाम बिहार राज्य अन्य अन्य आदि।[1987 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 83]; राज नारायण बनाम अधीक्षक, केंद्रीय जेल, नई दिल्ली [1970 (2) एस. सी. सी. 750]; राजेश मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** [1994 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 1085]; मधु लिमये और अन्य [1969 (1) एस. सी. सी. 292] पर भरोसा रखा गया है । यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया कि रिमांड आदेश अनिवार्य रूप से एक कानूनी आदेश होना चाहिए जिसे एक सक्षम न्यायिक अधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता हो। रीडर ऑफ कोर्ट

द्वारा एक प्रशासनिक आदेश न्यायिक हिरासत का विस्तार किया जा सकता है। [योगेश मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य; निर्णय दिनांक 09.01.2018 रि.या.(आप.) (आप.) सं. 3464/2017]।

13. यह तर्क दिया गया था कि हर्षद एस. मेहता बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [आप.] विविध (मुख्य) 2508/1992 और अमरजीत शर्मा बनाम विशेष कपट अन्वेषण कार्यालय[2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 3633], माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध हिरासत के मामले में, रिट याचिका वैधानिक उपचार नही है , बल्कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में या धारा 482 भा.दं.सं के तहत एक आवेदन दायर करना है। चूंकि वर्तमान मामले में, कोई न्यायिक आदेश नहीं है, न्यायिक हिरासत को 07.12.2023 तक विस्तृत करना है, स्वयं ही याचिकाकर्ताओं की तत्काल रिहाई की आवश्यकता है क्योंकि अवैध हिरासत के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस संबंध में गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी [(2022) 13 एस. सी. सी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया **542].मनुभाई रतिलाल पटेल के फैसले पर भी भरोसा जताया गया ।** त्र. उशाबेन बनाम गुजरात राज्य और अन्य [ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 313] द्वारा प्रस्तुत किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दर्ज करने तथा इस कार्यवाही को पूरा करने का उद्देश्य कार्यवाही को त्वरित और तकनीक से मुक्त करना है

क्योंकि स्वतंत्रता दांव पर है और याचिकाकर्ताओं के स्वतंत्रता के अधिकार का तत्काल निर्धारण होना चाहिए । यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त से व्यथित, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिकाएं दायर करने के लिए विवश है।

<u>प्रत्यर्थियों की प्रस्तुतियाँ</u>

14. उपरोक्त दलीलों का खंडन करते हुए, ईडी की ओर से उपस्थित विशेष वकील, श्री जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-05 के समक्ष 07.12.2023 को याचिकाकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेश किया गया था, न कि भौतिक रूप से, ऐसा 30.10.2023 को पारित आदेश के अनुसरण में किया गया जैसा कि जैसा कि याचिकाकर्ता हरिओम राय तथा उनके वकील ने जेल अधीक्षक से याचिकाकर्ता हरिओम राय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था । उसी को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-05 ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मौखिक अनुरोध/आवेदन को अगले आदेश तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेश करने की अनुमति दी। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं का मामला उसी दिन दोपहर 2 बजे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-04 की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालाँकि, अनजाने में अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद जब तक कि मामले को सुनवाई स्थगित कर दिया गया, याचिकाकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 के समक्ष पेश नहीं किया गया ।

उन परिस्थितियों में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 ने याचिकाकर्ताओं को पेशी वारंट जारी करने का निर्देश दिया और संज्ञान लेने के उद्देश्य से मामले को 13.12.2023 तक स्थगित करते हुए प्रसन्नता जाहिर किये । उन्होंने आगे कहा कि ईडी ने वर्तमान मामले में जांच की परिणति के बाद पहले ही 06.12.2023 को अभियोजन शिकायत दर्ज कर ली थी, इसलिए ईडी ने रिमांड बढ़ाने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया।

15. श्री हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता ईडी की हिरासत में नहीं थे, हालांकि, वे न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए उनकी हिरासत पूरी तरह से वैध है और अवैध नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। पेशी वारंट जारी करके सभी याचिकाकर्ताओं को पेश करने का आदेश अपने आप में यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि 07.12.2023 के रूप में याचिकाकर्ताओं की रिमांड अवैध नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को अगली तारीख के लिए पेश करने के आदेश को केवल न्यायिक हिरासत के विस्तार के रूप में माना जा सकता है, जब अभियोजक द्वारा रिमांड के लिए अनुरोध किया जाता है और आरोपी व्यक्तियों की ओर से इसका विरोध नहीं किया जाता है या उनकी ओर से कोई जमानत याचिका दायर नहीं की जाती है। मनोहारी बनाम राजस्थान राज्य [एम. ए. एन. यू./आर. एच./<आई. डी. 1] के मामले में निर्णय पर भरोसा जताया गया था।

16. श्री हुसैन ने आगे कहा कि अगली सुनवाई की तारीख के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ पेशी वारंट जारी करने का आदेश पारित करते समय सभी याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित वकीलों द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 के समक्ष किया गया था। किसी भी वकील ने याचिकाकर्ताओं को पेश करने के उक्त आदेश को पारित करने या विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 द्वारा उनकी जमानत के लिए अनुरोध करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इस प्रभाव के लिए, रघुनाथन चौहान बनाम राज्य [1980 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 103] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि सुनवाई की तारीख को अर्थात एक विशेष तारीख पर आरोपी को पेश करने का आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उस तारीख तक आरोपी को हिरासत में रखा गया था और पेशी वारंट के अनुसार उस तारीख को अदालत में पेश किया जाना था।

17. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि यथासंभव एक अभियुक्त को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या आरोपी की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक थी या नहीं, इस प्रकार, मजिस्ट्रेट द्वारा अनुपस्थिति में आरोपी व्यक्ति की रिमांड का एक नया आदेश रिमांड को अवैध नहीं बनाएगा। उक्त दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिए, **एम.**

सांबशिव राव बनाम भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य [एम. अन्य एन. यू./एस. सी./<आई. डी. 1], राज नारायण बनाम अधीक्षक, केंद्रीय जेल, नई दिल्ली [1970 (2) एस. सी. सी. 750], गौरी शंकर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य [(1972) 1 एस. सी. सी. 564] और संदीप कुमार डे बनाम प्रभारी अधिकारी, सखी जमशेदपुर और अन्य[(1974) 4 **एससीसी 273]** पर निर्भरता रखी गई।

18. यह भी प्रस्तुत किया गया कि किसी आरोपी को 15 दिनों से अधिक के लिए रिमांड देने के लिए नए रिमांड आदेश पारित करने की आवश्यकता सत्र न्यायालय पर लागू नहीं होती है, जिसकी शक्तियां धारा 309 दं.प्र.सं के तहत केवल 15 दिनों तक रिमांड देने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं। अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **कूमर इंद्रनील बनाम बिहार राज्य**, [2000 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 847] के मामले पर भरोसा किया है।

19. इसे आगे **कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट [(1974) 4 SCC 141**], के मामले में निर्णयों पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया गया था।, **गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय बनाम राहुल मोदी [2022 एसीसी ऑनलाइन ए सी 153], महाराष्ट्र राज्य बनाम तस्नीम रिजवान सिद्दीकी [(2018) 9 एस सी सी 745]** कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में न्यायालय को तारीख वापसी पर हिरासत की वैधता के संबंध में होना है। अंत में, यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में एक्टसक्यूरी नेमिनेम ग्रेवाबिट की कहावत लागू होती है जो

07.12.2023 से 13.12.2023 तक याचिकाकर्ताओं की हिरासत को मान्य करती है **[वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व उप निदेशकों और अन्य** द्वारा किया गया; एसएलपी (सीआरएल) संख्या 2284-2285/2023]।

20. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 14.12.2023 को , श्री जोहेब हुसैन, ईडी के लिए विशेष विद्वान वकील शारीरिक रूप से पेश हुए और श्री हरिहरन एन., याचिकाकर्ता एंड्रयू के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के अन्य वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए, और इस अदालत के समक्ष उल्लेख किया कि अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 ने याचिकाकर्ताओं की न्यायिक हिरासत को 13.12.2023 से 20.12.2023 (दोपहर 2 बजे) तक बढ़ा दिया था। दिनांकित 13.12.2023 के आदेश की प्रति पूरे बोर्ड को सौंपी गई थी और इसे रिकॉर्ड पर रखा गया है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

21. विस्तार से की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए, विशेष रूप से, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक असाधारण उपचार है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए उसे अवैध कारावास दिया गया होता है। आमतौर पर, एक सक्षम अदालत द्वारा रिमांड का आदेश अनिवार्य रूप से एक न्यायिक कार्य है और इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण

रिट के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक कि रिमांड आदेश में अधिकार क्षेत्र का अभाव न हो या पूरी तरह से अवैध न हो जिसके परिणामस्वरूप गैरकानूनी "हिरासत" न हो। यह सच है कि रिमांड के आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में चुनौती दी जा सकती है यदि ऐसा आदेश आत्यन्तिक रूप से यांत्रिक या आकस्मिक तरीके से पारित किया जाता है तब। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकीलों के इस तर्क को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि वैध हिरासत रिमांड कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है, जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत अवैध है, तो ऐसा व्यक्ति तुरंत रिहा होने का हकदार है।

22. हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को केवल कानून के अनुसार "हिरासत" में रखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 760]** के मामले में अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा पर विचार किया है और कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के पोषित उद्देश्यों में से एक है और उससे वंचित करना केवल विधिगत और तय प्रावधानों के अनुरूप ही हो सकता है।

23. उपरोक्त के आलोक में, धारा 167 (2) दं.प्र.सं और धारा 309 दं.प्र.सं के संदर्भ में रिमांड का आदेश पारित करने की न्यायिक अधिकारी की शक्ति से संबंधित वर्तमान याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे की सराहना करने के लिए, उपरोक्त प्रावधान इन याचिकाओं में शामिल मुद्दे को समझने के लिए प्रासंगिक हैं। इन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया हैः-

" धारा 167 प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं की जा सकती है।

(1) XXXX XXXX XXXX

(2) जिस मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत एक आरोपी व्यक्ति को भेजा जाता है, वह समय-समय पर, चाहे उसके पास मामले की सुनवाई करने की अधिकार क्षेत्र हो या न हो, ऐसे मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में लिए गये आरोपी को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है, और यदि उसे मामले की सुनवाई करने या मुकदमे के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और वह आगे हिरासत को अनावश्यक समझता है, तो वह आरोपी को ऐसे अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को भेजने का आदेश दे सकता हैः

बशर्ते कि-

(क) मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति के नज़रबंदी को अधिकृत कर सकता है, अन्यथा यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो पुलिस की हिरासत में, पंद्रह दिनों की अवधि से ज्यादा दिनों के लिए रख सकता है , लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस पैराग्राफ के तहत अभियुक्त व्यक्ति को कुल अवधि से अधिक के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं रहेगा ।

(i) नब्बे दिन, जहां जांच मौत, आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के कारावास तक दंडनीय अपराध से संबंधित है;

((ii) साठ दिन, जहां जाँच किसी अन्य अपराध से संबंधित है, और, नब्बे दिन, या साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर, जैसा भी मामला हो, आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि वह जमानत के लिए तैयार है और जमानत प्रस्तुत करता है, और इस उप-धारा के तहत जमानत पर रिहा किए गए प्रत्येक व्यक्ति को उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत रिहा किया गया माना जाएगा;

(ख) कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत पुलिस की हिरासत में अभियुक्त को तब तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को पहली बार उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है और बाद में हर बार जब तक कि आरोपी पुलिस की हिरासत में नहीं रहता है, लेकिन मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज द्वारा पेश करने पर न्यायिक हिरासत में और हिरासत बढ़ा सकता है।

(ग) द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से शक्ति प्राप्त नहीं है, पुलिस की अभिरक्षा में नज़रबंदी को अधिकृत नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण I..- संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि, पैराग्राफ (क) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बावजूद, अभियुक्त को हिरासत में तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं देता है।

स्पष्टीकरण II.- यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति को खंड (ख) के अधीन यथा अपेक्षित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, तो अभियुक्त व्यक्ति का उत्पादन निरोध को

प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से अभियुक्त व्यक्ति को प्रस्तुत करने के आदेश द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। **बशर्ते कि** अठारह वर्ष से कम आयु की महिला के मामले में, नज़रबंदी को रिमांड होम या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थान की अभिरक्षा में रहने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

<u>"धारा 309-कार्यवाही को अग्रगामी एवं स्थगित करने की शक्ति</u>

1. प्रत्येक जांच या मुकदमे में कार्यवाही दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, जब तक कि अदालत को कारण दर्ज करने के लिए अगले दिन से आगे का स्थगन आवश्यक न लगे।

जब जांच या मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क , धारा 376 क ख , धारा 376ख , धारा 376 ग या धारा 376घ , धारा 376घ क , धारा 376घ क के तहत किसी अपराध से संबंधित हो, तो जांच या मुकदमा आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

2. यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान लेने या विचारण शुरू करने के बाद, किसी जांच या विचारण के प्रारंभ को स्थगित करना या स्थगित करना आवश्यक या उचित समझता है, तो वह समय-समय पर, दर्ज किए जाने के कारणों से, उसे ऐसी शर्तों पर स्थगित या स्थगित कर सकता है जो वह उचित समझता है, ऐसे समय के लिए जो वह उचित समझता है, और यदि अभिरक्षा में हो तो अभियुक्त को वारंट द्वारा रिमांड कर सकता हैः

बशर्ते कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस खंड के तहत एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं भेजेगाः

बशर्ते कि जब गवाह उपस्थित हों तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर, उनकी जांच किए बिना कोई स्थगन या स्थगन नहीं दिया जाएगाः

बशर्ते कि केवल अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण दिखाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि -

1. किसी पक्ष के अनुरोध पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, सिवाय इसके कि परिस्थितियाँ उस पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों।

2. तथ्य यह है कि एक पक्ष का वकील दूसरे न्यायालय में लगा हुआ है, स्थगन के लिए आधार नहीं होगा;

3. जहाँ कोई गवाह न्यायालय में उपस्थित है लेकिन कोई पक्षकार या उसका वकील उपस्थित नहीं है या पक्षकार या उसका वकील यद्यपि न्यायालय में उपस्थित है, गवाह की जाँच या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, न्यायालय, यदि उचित समझता है, तो गवाह का बयान दर्ज कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह, जैसा भी मामला हो, गवाह की परीक्षा-इन-चीफ या प्रतिपरीक्षा के साथ प्रदान करता है।

व्याख्याएँ

1. यदि यह संदेह करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त किए गए हैं कि आरोपी ने कोई अपराध किया है, और यह संभावना प्रतीत होती है कि रिमांड द्वारा और सबूत प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यह रिमांड के लिए एक उचित कारण है।

2. जिन शर्तों पर आगे बढाया जा सकता है या स्थगन दिया जा सकता है, उनमें उचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा लागत का भुगतान शामिल है।"

24. जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट होगा, रिमांड की शक्ति अदालत में निहित है, जांच के आरंभिक चरण में, सबसे पहले गिरफ्तार व्यक्ति

को या तो पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। जबकि, धारा 309 भा.दं.संहिता के तहत हिरासत रिमांड केवल जांच के समापन पर संज्ञान के बाद के चरण में संचालित होती है जब अदालत के समक्ष आरोप पत्र रखा जाता है।

वर्तमान याचिकाओं में, वास्तव में, शुरू में पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद, याचिकाकर्ताओं को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -05 की न्यायालय द्वारा धारा 167 (2) दं.प्र.सं के तहत समय-समय पर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा था।

25. गौरतलब है कि यह विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 द्वारा 07.12.2023 को पारित आदेश है, याचिकाकर्ताओं के अनुसार जो जारी है, याचिकाकर्ताओं की न्यायिक हिरासत को मान्य करने के लिए आदेश को समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को आदेश पारित करते समय विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 के समक्ष पेश नहीं किया गया था जो धारा 167 (2) (ख) के विपरीत है और संज्ञान के बाद का चरण शुरू नहीं हुआ क्योंकि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 ने अभियोजन शिकायत का संज्ञान नहीं लिया, इसलिए, याचिकाकर्ताओं की हिरासत रिमांड को कानून के अनुसार विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 द्वारा नहीं बढ़ाया गया था, परिणामस्वरूप, उसके बाद से याचिकाकर्ताओं की अवैध हिरासत हुई। प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश द्वारा पारित दिनांक 07.12.2023 के आदेश को पुन: प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा, जो यहां नीचे दिया गया है: -

स्थानांतरण के माध्यम से प्राप्त शिकायत प्रस्तुत करें। इसका परीक्षण और पंजीकरण किया जाए।

प्रस्तुत : श्रीमान साइमन बेंजामिन और श्री मनीष जैन, आईडी. विशेष पीपी प्रवर्तन निदेशालय के लिए ।

श्रीमान विक्रम चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता (वी. सी. के माध्यम से) एस. एच. के साथ। अभयराज, अभियुक्त हरि ओम राय की ओर से (धारा संख्या 20 पर)।

श्रीमान अंकित भाटिया और समर, अभियुक्त नितिन गर्ग (धारा सं. 21) के विद्वान् वकील।

एस. श्री के साथ प्रियंक तन्मय शर्मा और शित्ज अभियुक्त ग्वांगवेन कुआंग @एंड्रयू के लिए विद्वान् परामर्शदाता (धारा सं . 4) पर।

श्री हर्ष यादव, अभियुक्त राजन मलिक के विद्वान् वकील (धारा संख्या 15 पर)।(ताजा वकालतनामा दाखिल किया गया)

चारों आरोपी तिहाड़ जेल में जेसी में बताए गए हैं । वे आज पेश नहीं किये गये ।

शेष अभियुक्त व्यक्ति कंपनियाँ और व्यक्ति हैं और कहा जाता है कि उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सहायक निदेशक (धन शोधन निवारण अधिनियम), तरुण कुमार भारद्वाज, प्रवर्तन अधिकारी अरुण खत्री के साथ।

यह संबंधित बचाव पक्ष के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें शिकायत और संबद्ध दस्तावेजों की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। यह विशेष पीपी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की और से प्रस्तुत किया गया है कि अदालत द्वारा शिकायतकर्ता पर संज्ञान लेने के बाद शिकायत और दस्तावेजों को आरोपी व्यक्तियों को सपुर्द की जा सकती है। विद्वान परामर्शदाता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में दस्तावेज 16 ट्रंक में भरे दस्तावेज है। वह इस संबंध में निर्देश चाहता है कि दस्तावेज़ों को जाँच के लिए अहलमाद को यह कब सौंपा जाए। 09.12.2023 को जांच के लिए दस्तावेज़ों को अहलमाद को सौंप दिया जाए।

अहलमद कमरे में उस स्थान की पहचान करेगा जहाँ उक्त 16 ट्रंक रखी गयी है ।

संज्ञान के पहलू पर विचार के लिए दोपहर 2 बजे 13.12.2023 पर रखें।

एन. डी. ओ. एच. के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ पेशी वारंट जारी करें।

अभियुक्त व्यक्तियों को दोपहर 2 बजे 13.12.2023 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश किया जाए। आदेश की प्रति को प्रार्थना के अनुसार दस्ती दी जाए।"

26. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को अदालत में पेश नहीं किया गया था, भले ही दिन में पहले, उन्हें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-05 के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेश किया गया था, लेकिन अदालत द्वारा लिखित रूप में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।इसके अलावा, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 ने अभियोजन पक्ष की शिकायत का संज्ञान नहीं लिया और इसे सुनवाई की तारीख अगली तारीख तक स्थगित कर दिया, जिससे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पेशी वारंट जारी किए गए।जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है, वह याचिकाकर्ताओं की "अभिरक्षा" की प्रकृति के बारे में है, चाहे वह उपरोक्त आदेश को देखते हुए वैधानिक हो या अवैधानिक ।

27. इस पृष्ठभूमि में, हम सुरेश कुमार भीकमचंद जैन (पूर्वोक्त) के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जिसमें शामिल मुद्दों में से एक धारा 167 (2) के तहत परिकल्पित अवधि से परे भी रिमांड के आदेश पारित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के बारे में था । उक्त मामले में, आरोप पत्र दायर किए जाने के बावजूद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत आरोपी को पेश

करने के लिए "मंजूरी" प्राप्त करने में अभियोजन पक्ष की विफलता के कारण विशेष अदालत द्वारा इसके आधार पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। हालाँकि, विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा 309 दं.प्र.सं. के तहत विचार किए गए मंच पर आगे बढ़े बिना रिमांड आदेश पारित करना जारी रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

> "18. उक्त मामलों में से कोई भी इस स्थिति से अलग नहीं है कि एक बार निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दायर करने के बाद, डिफ़ॉल्ट जमानत या वैधानिक जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारे विचार में, आरोप-पत्र दाखिल करना इस मामले में धारा 167 (2) (क) (ii) के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है। जहां तक धारा 167 दं.प्र.सं. का संबंध है, संज्ञान लिया जाता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है । याचिकाकर्ता को जो अधिकार प्राप्त हुआ होगा, यदि आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया था, वह इस मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं है। केवल इसलिए कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने और धारा 309 दं.प्र.सं. के चरण तक आगे बढ़ने के लिए मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त वैधानिक जमानत देने का हकदार है, जैसा कि धारा 167दं.प्र.सं. में परिकल्पित है। एक अभियुक्त को किसी अदालत की हिरासत में रहना पड़ता है। जाँच की अवधि के दौरान, अभियुक्त मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है जिसके सामने उसे पहले पेश किया जाता है। उस चरण के दौरान, धारा 167 (2) दं.प्र.सं. के तहत, मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को पुलिस हिरासत और/या न्यायिक हिरासत दोनों के लिए, एक बार में 15 दिनों के लिए, 10 साल से कम के दंडनीय अपराधों के मामलों में अधिकतम 60 दिनों की अवधि और 10 साल से अधिक के लिए दंडनीय अपराध हैं या यहां तक कि मौत की सजा भी है तो 90 दिनों के लिए अपराध हिरासत में भेजने का अधिकार निहित है । यदि कोई जांच प्राधिकरण निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर करने में विफल रहता है, तो आरोपी वैधानिक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

> ऐसी स्थिति में, अभियुक्त तब तक मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में रहता है जब तक कि अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, जब उक्त न्यायालय खंड 309 दं.प्र.सं. के संदर्भ में मुकदमे के दौरान रिमांड के उद्देश्यों के लिए अभियुक्त की अभिरक्षा ग्रहण करता है। दोनों चरण अलग-अलग हैं, लेकिन एक दूसरे का अनुसरण करते हैं ताकि अदालत के साथ अभियुक्त की अभिरक्षा की निरंतरता बनाए रखी जा सके।"

28. **गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय** (पूर्वोक्त) के मामले में, **सुरेश कुमार भीकमचंद** (पूर्वोक्त) के फैसले पर भरोसा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त तब तक मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है।"

29. उपरोक्त चर्चाओं से दो स्थितियाँ सामने आई हैं जब न्यायालय में आरोप पत्र/अभियोजन शिकायत दायर की जाती है। एक है, जब धारा 167 (2) दं.प्र.सं. के तहत रिमांड की अवधि समाप्त नहीं हुई है और इस बीच जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र/अभियोजन शिकायत दायर की जाती है और सक्षम अदालत उक्त आरोप पत्र/अभियोजन शिकायत पर धारा 309 दं.प्र.सं. के तहत संज्ञान लेती है। संज्ञान लेने की तारीख को, आरोपी को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जाता है और उसे धारा 309 दं.प्र.सं. के तहत न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाता है । हालाँकि, न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ पेशी वारंट सुनवाई के तारीख के अगली वाली तारीख को जारी किया गया

। धारा 167 दं.प्र.सं के तहत इस रिमांड की वैधता को न्यायालय में पहले **सुनील कुमार शर्मा बनाम दिल्ली आई. एल. आर. के एन. सी. टी. राज्य[(2005) II दिल्ली 153]** के मामले में चुनौती दी गई थी।

30. उक्त मामले में, धारा 167 दं.प्र.सं. के तहत एक वैध आदेश की अवधि के दौरान, आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखा गया था, उसकी रिमांड 26.04.2005 तक जारी रखी जानी थी, हालांकि, 25.04.2005 पर आरोप पत्र दायर किया गया था और मजिस्ट्रेट ने उसी दिन आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जब आरोपी 26.04.2005 तक न्यायिक हिरासत में था। उसी तारीख के लिए उनके खिलाफ पेशी वारंट जारी किए गए थे। 25.04.2005 को अवैध अभिरक्षा पर विचार करने वाले अभियुक्त की ओर से उठाई गई आपत्ति यह थी कि धारा 167 (2) दं.प्र.सं. के तहत या 25.04.2005 को या 26.04.2005 को धारा 309 (2) दं.प्र.सं. के तहत रिमांड के लिए कोई वैध आदेश पारित नहीं किया गया था।

यह तर्क दिया गया कि 20.04.2005 को पारित रिमांड का आदेश वह था जो जांच के विचाराधीन रहने के दौरान पारित किया गया था और तदनुसार यह धारा 309 दं.प्र.सं. के तहत 25.04.2005 को अपराध पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेते हुए स्वतः ही समाप्त हो गया ।

> "जहां आरोप-पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उसके ठीक बाद आरोपी को धारा 309 (2) दं.प्र.सं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, वहां कोई समस्या नहीं होती है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि [दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत] एक अवधि का अंत बिना किसी अंतराल के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 (2) के तहत रिमांड की अवधि में " निकल" जाएगा। तथापि, जहां आरोप-पत्र दाखिल किए जाने पर संज्ञान लेते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 (2) के तहत रिमांड का आदेश तुरंत पारित नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत एक वैध नज़रबंदी का आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 (2) के तहत हिरासत के लिए आदेश और रिमांड के बीच एक खाई प्रतीत होती है। लेकिन, वास्तव में ऐसा कोई "विराम" नहीं है।ऐसा केवल इस धारणा के कारण है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत पारित रिमांड आदेश का संज्ञान लेता है, वह समाप्त हो जाता है ।यह धारणा गलत है। एक बार आरोप पत्र दायर होने और संज्ञान लेने के बाद, यह सच है कि जांच समाप्त होने के बाद, धारा 167 (2) के तहत शक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 167 (2) के तहत वैध रूप से दिया गया आदेश उस समय समाप्त हो जाता है जब आरोप-पत्र दायर किया जाता है और संज्ञान लिया जाता है। ऐसा आदेश तब तक वैध होगा जब तक कि यह अवधि समाप्त नहीं हो जाती है या जब तक कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 (2) के तहत रिमांड आदेश द्वारा नहीं हो जाता है, जो भी समय में पहले हो।"

31. दूसरी स्थिति यह है कि जब आरोप पत्र/अभियोजन की शिकायत सक्षम अदालत के समक्ष दायर की जाती है और अदालत द्वारा धारा 309 दं.प्र.सं. के तहत संज्ञान नहीं लिया जाता है। हालाँकि, उक्त आरोपी की रिमांड मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत जारी रहती है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेश कुमार भीकमचंद जैन (पूर्वोक्त)** ने देखा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई रिमांड वैध थी और आरोपी संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान लिए

जाने तक मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहा। यह भी माना जाता है कि ऐसी स्थिति में आरोपी को "किसी अदालत" के लिए हिरासत में रहना पड़ता है।

32. उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की कुछ अदालतें विशेष कानूनों से निपटने वाली नामित अदालतें हैं और ऐसी अदालतों को धारा 167 के तहत किसी भी विशेष जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच के दौरान निर्धारित अधिकतम अवधि तक रिमांड देने और आरोप पत्र/अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेने और कानून द्वारा विचार के अनुसार मुकदमा चलाने और इस प्रकार धारा 309 के तहत रिमांड देने का अधिकार है। वर्तमान मामले में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 की अदालत ऐसी ही एक अदालत है।

33. श्री हुसैन ने तर्क दिया था कि ईसीआईआर के संबंध में जांच समाप्त हो गई थी, इसलिए, अभियोजन पक्ष की शिकायत 06.12.2023 पर अदालत में दायर की गई थी।अतिरिक्त सत्र न्यायधीश .-04 द्वारा 07.12.2023 पर याचिकाकर्ताओं के पेशी वारंट जारी करने का आदेश पर्याप्त है और चूंकि याचिकाकर्ताओं को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था, इसलिए यह याचिकाकर्ताओं की विस्तारित अभिरक्षा को 07.12.2023 से 13.12.2023 तक मान्य करता है।

34. वर्तमान रिट याचिकाओं में, धारा 309 दं.प्र.सं. के तहत आवश्यक 07.12.2023 को कोई संज्ञान नहीं लिया गया था क्योंकि ई. डी. ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 के समक्ष प्रस्तुत किया था कि इस मामले से

दस्तावेज भारी संख्या में थें , जिन्हें 16 ट्रंकों में रखा गया था। अदालत के अहलमाद द्वारा दस्तावेजों की जांच की जानी थी और विद्वान **अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04** ने ईडी को निर्देश दिया कि वह दस्तावेजों को अहलमाद को 09.12.2023 को जांच के लिए सौंप दे और मामले को 13.12.2023 को संज्ञान के पहलू पर विचार के लिए दोपहर 2 बजे स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ताओं की न्यायिक हिरासत 07.12.2023 को समाप्त हो रही थी, हालाँकि, वर्तमान रिटों से उभरने वाले विशिष्ट और भिन्न तथ्य और परिस्थितियाँ यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 के समक्ष पेश नहीं किया गया था। इन सभी याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित वकीलों द्वारा किया गया था और याचिकाकर्ताओं के पेशी वारंट के आदेश के संबंध में किसी भी वकील द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला नहीं है कि ईडी द्वारा अभियोजन शिकायत निर्धारित अवधि से अधिक दायर की गई थी जिससे याचिकाकर्ताओं को "डिफ़ॉल्ट जमानत" का अधिकार मिल गया । साथ ही उस समय किसी भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई जमानत याचिका दायर नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ताओं को "अदालत की हिरासत" में रहना पड़ता है। इस प्रकार, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-04 ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई की तारीख के अगली वाली तारीख को अदालत में पेश करने के लिए पेशी वारंट जारी करने का सही निर्देश दिया। अभिलेख के अनुसार, उक्त

पेशी वारंट 13.12.2023 को याचिकाकर्ताओं को पेश करने के लिए 09.12.2023 पर जारी किए गए थे।

35. हम अपने सामने एक सवाल रखते हैं, यह मानते हुए कि एक सक्षम अदालत ने आरोप पत्र/अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है और मामले को कार्यवाही/मुकदमे के एक विशेष चरण में रखा है, हालांकि, सुनवाई की तारीख उक्त तिथि पर, उस मामले में आरोपी को किसी अपरिहार्य कारण से न्यायिक हिरासत से पेश नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में अदालत उक्त आरोपी के खिलाफ पेशी वारंट जारी करती है और मामले को सुनवाई की तारीख के अगले तारीख को रखा जाता है। क्या यह कहा जा सकता है कि उस अवधि के दौरान, जब अभियुक्त को सुनवाई की तारीख अंतिम तिथि पर पेश किया गया था और उसे पेशी वारंट के निष्पादन में सुनवाई की तारीख अगली तारीख को अदालत के समक्ष पेश किया जाना है, उसकी न्यायिक हिरासत अवैध है। हमारे विचार से इसका उत्तर नकारात्मक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अभियुक्त की हिरासत में निरंतरता है और ऐसे अभियुक्त की अभिरक्षा में कोई "विराम" नहीं है। हालाँकि, स्थिति तब अलग होगी जब आरोपी को सुनवाई की तारीख पर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है और सुनवाई की तारीख के अगले उसी तारीख को उक्त आरोपी के लिए कोई पेशी वारंट जारी नहीं किया जाता है, लेकिन बाद में जारी किया जाता

है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की अभिरक्षा निरंतर नहीं रहेगी और अवकाश अवधि के लिए यह अवैध हो सकता है।

36. हम, इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई प्रस्तुतियों को बनाए रखने में असमर्थ पाते हैं कि याचिकाकर्ता 07.12.2023 के बाद से अवैध हिरासत का सामना कर रहे हैं।विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 ने याचिकाकर्ताओं को पेश करने के लिए 07.12.2023 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है और याचिका कर्ता विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश -04 की कानूनी हिरासत में रहते हैं।

37. प्रस्तुतियाँ और रिट याचिकाओं में व्यक्त किए गए विचारों का कोई सार नहीं हैं। तदनुसार, वही निरस्त किये जाते हैं । लंबित आवेदन भी निरस्त किये जाते हैं।

न्या. शालिन्दर कौर,

न्या.सुरेश कुमार कैत,

19 दिसंबर, 2023
एसयू

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*